International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science (IJEMMASSS)
ISSN : 2581-9925, Impact Factor: 6.882, Volume 04, No. 02(II), April - June, 2022, pp. 85-88

राजस्थान की खेल नीति (2019–20): एक समीक्षात्मक अध्ययन

प्रो. बी.एल. दायमा*
बाबूलाल चौधरी**

सार

स्वतंत्रता के पश्चात् से भी विभिन्न सरकारों द्वारा लोगों को स्वस्थ बनाने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं के साथ–साथ खेलों को बढ़ावा देने के लिए कई प्रयास किये गये। खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अर्न्तराष्ट्रीय स्तर की स्पर्द्धाओं में बेहतर प्रदर्शन और खेलों को बढ़ाने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार द्वारा खेल नीति का निर्माण किया गया। केन्द्र सरकार की तरह ही राजस्थान में खेल को बढ़ावा देने और युवाओं को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा 'राज्य खेल नीति – 2019–20' की घोषणा की गई जिसके तहत विभिन्न खेलों हेतु संरचना के विकास के साथ–साथ खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने हेतु कई घोषणाएं की गई। प्रस्तुत लेख में राजस्थान सरकार की खेल नीति का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।

शब्दकोशः *शारीरिक शिक्षा, खेल नीति, प्रशिक्षण।*

प्रस्तावना

प्राचीनकाल से ही शारीरिक शिक्षा को दैनिक जीवन शैली का अभिन्न अंग माना जाता था। उस काल में कई प्राचीन ग्रामीण खेल प्रचलन में थे लेकिन इसके साथ ही शारीरिक श्रम लोगों की दैनिक कार्यशैली का हिस्सा थे। प्राचीनकाल में कृषि ही लोगों का मुख्य पारिवारिक व्यवसाय था और घर पुरूष सदस्यों के साथ महिलाएं भी घर के दैनिक कार्यों के साथ–साथ कृषि कार्य में हाथ बंटाती थी। पुरूष अधिकांश जीवनयापन के लिए ऐसे कार्य किया करते थे जिनमें शारीरिक श्रम निहित होता था तो दूसरी ओर महिलाएं भी फसल काटना, ईंधन के लिए लकड़िया बीनना, कुओं से पानी भरना जैसे कार्य करती थी जिनमें उनका शारीरिक व्यायाम हो जाता था।

इस प्रकार प्राचीनकाल में दैनिक दिनचर्या में शारीरिक श्रम निहित होता था लेकिन आज की भाग–दौड़ भरी नगरीय जिंदगी और बढ़ते काम के दबाव के कारण व्यक्ति शारीरिक विकास पर उचित ध्यान नहीं दे पा रहा है। वर्तमान कम्प्युटर युग में दैनिक दिनचर्या के शारीरिक श्रम कम होता जा रहा है लोग अधिकांश समय कम्प्युटर और मोबाईल के सामने बैठे रहते हैं। एक ओर जहां राज्य में खेल संरचनाओं की कमी है या वे विकसित नही है तो दूसरी ओर व्यक्ति का ध्यान रोजगार के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करने में लगा हुआ है जिसके कारण वह अपने शारीरिक विकास के लिए खेलों पर ध्यान केन्द्रित नही कर पा रहा है। यही कारण है कि राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न खेलों में राज्य की भागीदारी संतोषजनक नहीं कही जा सकती है।

* शारीरिक शिक्षा विभाग, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर, राजस्थान।
** शोधार्थी, शारीरिक शिक्षा विभाग, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर, राजस्थान।

खेल नीति

आज भारत के कई खिलाड़ी राष्ट्रीय और अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर अपने देश का नाम रोशन कर रहे हैं। आज के तकनीकी युग में खिलाड़ियों को खेल की बारिकीयों को समझने के लिए बेहतर प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है और इसके साथ ही उनको बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाना भी आवश्यक है ताकि वे अपनी पूरी क्षमता से खेलों में अपना प्रदर्शन कर सके। साथ ही खिलाड़ियों के बेहतर भविष्य के लिए उनके लिए रोजगार एवं अन्य सुविधाओं की आवश्यकता है। इसी उद्देश्य से केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा समय–समय पर 'खेल नीति' का निर्माण किया गया। राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खेलों बेहतर प्रदर्शन हेतु खिलाड़ियों को उचित सुविधाएं प्रदान करना एवं प्रशिक्षित करना आवश्यक है। आज राज्य में शहरी क्षेत्रों में भी खेलों के आधुनिक संसाधन (सुविधाएं) नहीं है तथा खिलाड़ियों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन्हीं समस्या को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा 2019–20 में नई 'खेल नीति' की घोषणा की राज्य में खेल संरचनाओं का विकास हो सके और खिलाड़ी हर स्तर पर बेहतर प्रदर्शन कर सके।

नई खेल नीति के तहत राज्य सरकार द्वारा पूरे प्रदेश में व्यवस्थित एवं योजनाबद्ध तरीके से खेलों हेतु आधारभूत संरचना एवं खेल संरचनाऐं विकसित करने का लक्ष्य रखा गया। साथ ही नई खेल नीति में खिलाड़ियों को प्रशिक्षण के साथ–साथ आर्थिक सहयोग का भी प्रावधान किया गया ताकि वे राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का नाम रोशन कर सके।

खेल नीति (2019–20) के प्रमुख उददेश्य

- नई खेल नीति का प्रमुख उद्देश्य उभरते हुए प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को खेलों में पर्याप्त अवसर उपलब्ध करवाना है ताकि प्रदेश को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल सके।
- प्रदेश में खेलों के लिए उचित वातावरण तैयार करना ताकि युवाओं की खेलों के प्रति रूचि बढ़े और उनको खेलों के प्रति आकर्षित किया जा सके।
- खेल नीति का मुख्य उद्देश्य राज्य में खेलों के लिए एक ऐसी आधारभूत संरचना का निर्माण करना है जिससे अधिक से अधिक लोगों को उसका लाभ मिल सके।
- कई प्रतिभावान खिलाड़ी उचित सुविधाओं जैसे ठहरने, भोजन, यात्रा भत्ता जैसी मूलभूत आवश्यकताओं के अभाव में खेल प्रतिस्पर्द्धाओं में भाग लेने से वंचित रह जाते हैं। इस खेल नीति का उद्देश्य अधिक से अधिक खिलाड़ियों विशेषकर जो दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, उनके लिए मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करनावा है ताकि ऐसे प्रतिभावान खिलाड़ी जो अपनी आर्थिक स्थिति के कारण आगे नहीं आ पा रहे हैं, वे खेलों में आगे बढ़ सके।
- खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार और पुरस्कार प्रदान करना ताकि वे खेल में बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित हो सके।
- राज्य में खेलों के विकास के लिए समय–समय पर ब्लॉक, जिला एवं राज्य स्तर पर विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित करना ताकि प्रतिभावान खिलाड़ियों को राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पद्धाओं हेतु तैयार किया जा सके।

खेल नीति 2019–20 के मुख्य बिन्दु

- **आधारभूत संरचना का विकास**

राजस्थान में खेलों में आधारभूत संरचनाओं के विकास हेतु पूर्व में 'समन्वित स्टेडियम (आधारभूत खेल सुविधाएं) कार्यक्रम–2007' आंरभ किया गया था जिसके अन्तर्गत संभाग, जिला एवं तहसील स्तर पर स्टेडियम एवं अन्य खेल संरचनाओं के निर्माण कार्य कराने का लक्ष्य रखा गया था। इसके पश्चात् वर्ष 2015 में ग्रामीण स्तर पर स्टेडियम और आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए 'समन्वित स्टेडियम (आधारभूत खेल सुविधाऐं) कार्यक्रम–2015' का शुभारंभ किया गया था। इस योजना के अन्तर्गत संभाग, जिला एवं उपखण्ड स्तर के अतिरिक्त पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत स्तर पर मूलभूत आधारभूत संरचना के निर्माण कार्य का प्रावधान किया गया।

- **प्रशिक्षण सुविधाएं**

नई खेल नीति में राज्य के सभी जिलों में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रशिक्षित करने के लिए विशेष बल दिया गया है। वर्तमान में जिला स्तर पर राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के प्रशिक्षक और भारतीय खेल प्राधिकरण के प्रशिक्षक खिलाड़ियों के प्रशिक्षण दे रहे हैं और नई खेल नीति के अन्तर्गत प्रशिक्षण की इस व्यवस्था को ब्लॉक स्तर तक ले जाने की व्यवस्था की गई है जिससे ग्राम स्तर पर प्रतिभावान खिलाड़ियों को प्रशिक्षण मिल सके और वे राष्ट्रीय और अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर राज्य का नाम रोशन कर सके।

खेल नीति में राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए राजस्थान के खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करने के लिए प्रशिक्षण शिविर लगाने के साथ जिला स्तर पर प्रतिभाखोज प्रशिक्षण शिविर लगाने का प्रावधान किया गया। इसके अतिरिक्त 17 वर्ष तक उदीयमान प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के विकास के लिए ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर की व्यवस्था की गई है।

- **पुरस्कार एवं सम्मान**

नई खेल नीति में खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए नकद पुरस्कार देने का प्रावधान किया गया। खेल नीति में ओलम्पिक गेम्स में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले को 3 करोड़, रजत पदक जितने वाले को 2 करोड़ एवं कांस्य पदक जीतने वाले को 1 करोड़ रूपये की नकद राशि देने का प्रावधान किया गया। एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले को 1 करोड़, रजत पदक जीतने वाले को 60 लाख एवं कांस्य पदक जीतने वाले को 30 लाख रूपये का नकद पुरस्कार देने की घोषणा की गई। इन प्रतियोगिताओं के अतिरिक्त अन्य किसी अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर 5 लाख, द्वितीय स्थान प्राप्त करने पर 3 लाख तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने पर 2.5 लाख तक अनुदान देने की घोषणा की गई। राष्ट्रीय स्तर की स्पर्द्धाओं में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले को 2 लाख, द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले को 1.5 लाख और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को 1.25 लाख और राज्य स्तर की विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले को 1 लाख, द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले को 50 हजार और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को 30 हजार देने का प्रावधान किया गया।

- **राजकीय नौकरी में आरक्षण**

आज के युग में अधिकांश खिलाड़ी अपने भविष्य को लेकर शंकित रहते है और यही कारण है कि आज माता–पिता बच्चों को अपना ध्यान खेलों से हटाकर पढ़ाई पर लगाने की सलाह देते हैं ताकि वे अच्छा रोजगार प्राप्त कर अपना भविष्य उज्ज्वल बना सके। आज सभी सरकारों द्वारा खिलाड़ियों के बेहतर भविष्य के लिए उनको विभिन्न सरकारी पदों में आरक्षरण देने का प्रावधान किया गया है ताकि वे अपने भविष्य के प्रति निश्चित होकर पूरा ध्यान खेलों पर केन्द्रित कर सके।

राजस्थान सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति और भारतीय ओलम्पिक संघ द्वारा मान्यता प्राप्त खेलों जैसे – बैडमिंटन, टेनिस, शतरंज में एशियाई खेलों, एशियाई चैम्पियनशिप, राष्ट्रमण्डल खेलों, विश्व चैम्पियनशिप, दक्षेश खेलों और ओलम्पिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ी जिन्होंने व्यक्गित एवं टीम स्पर्द्धा में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को राजस्थान लोक सेवा आयोग के अधीन राजकीय सेवाओं में 2 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है। यह व्यवस्था राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद से प्राप्त खेल संघों एवं भारत सरकार द्वारा आयोजित विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं पर भी लागू होगी।

- **खिलाडी पेंशन योजना**

नई खेल नीति में राष्ट्रीय एवं अंतराष्ट्रीय स्तर पर पदक प्राप्त करने वाले एवं ओलम्पिक खेलों में प्रतिनिधित्व किया हो, ऐसे खिलाड़ियों को 40 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद द्वारा पेंशन की घोषणा की गई जिससे खिलाड़ी अपने भविष्य को लेकर निश्चिंत हो जाए और खेल पर अपना पूरा ध्यान केन्द्रित कर सके।

निष्कर्ष

राजस्थान के कई खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय एवं अंतराष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का नाम रोशन किया है। राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में छुपी हुई खेल प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद द्वारा नई खेल नीति की घोषणा की गई जिसमें जिला एवं ब्लॉक स्तर पर उपलब्ध खेल संरचनाओं का विस्तार ग्राम स्तर तक करने का निर्णय किया गया ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में छुपी हुई खेल प्रतिभाओं को आगे लाया जा सके। इस नीति में खेल संरचनाओं और आधारभूत संरचनाओं का भी ग्राम पंचायत स्तर तक विस्तार करने का प्रावधान किया गया।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. अटवाल हरभजन सिंह एवं यादव आर.के., भारत में शारीरिक शिक्षा का इतिहास, अमित ब्रदर्स पब्लिकेशन, नागपुर, 2006।
2. आक्सले चार्ल्स, खेलों में शारीरिक शिक्षा, स्पोर्ट्स पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2006।
3. राज्य की नई खेल नीति (2019–20), युवा मामले एवं खेल विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. राजस्थान सरकार, कार्मिक विभाग की अधिसूचना सं. एफ15(3)डीओपी/ए–प्प/2013/ पार्ट जयपुर दिनांक 03.07.2017।

❖◆❖